Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

सितम्बर (संग्रह)

2023

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **4**

- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 4
- मध्य प्रदेश के दो ग्रामों को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मिलेंगे अवॉर्ड्स 5
- रीवा में खुलेगा संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र 6
- मनरेगा कार्यक्रमों के लिये जलवायु सूचना सेवा टूल- U-CRISP का मेपकास्ट परिसर में लोकार्पण हुआ 6
- वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी 'माउंट एल्ब्रूज'पर लहराया तिरंगा 8
- एशियन गेम्स-2022 में मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ियों का चयन 8
- मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी 9
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए प्रदेश के पाँच शिक्षक 10
- साँची बनी देश की पहली सोलर सिटी 11
- नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने की अधिसूचना जारी 12
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित 13
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय 14
- राज्यपाल मंगुभाई पटेल लंदन में होंगे सम्मानित 14
- न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में छाया दमोह का शिवम छिरोलिया 15
- राष्ट्रपति मुर्मु ने कृषक लहरी बाई को 'पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान'से किया सम्मानित 16
- मध्य प्रदेश में शुरू होगा पहला सहकारिता विश्वविद्यालय 17
- एग्पा, भोपाल में मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का शुभारंभ 17
- लाडली बहनों को घरेलू गैस कनेक्शन गैस सिलेंडर रिफिल 450 रुपए में मिलेगा 18
- प्रख्यात चिकित्सा शोध जर्नल 'द लानसेट' का अब मध्य प्रदेश में हिन्दी में भी होगा प्रकाशन 20
- प्रधानमंत्री ने बीना में 51 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया 20
- मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान 21
- मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना'का शुभारंभ किया 22
- प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का किया शुभारंभ 23

नोट :

- प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिये संचालित छात्रावासों की रैंकिंग में सीहोर ज़िला प्रथम 24
- 10वें विज्ञान मेले में एम.पी. ट्रांसको के स्टाल को मिला द्वितीय पुरस्कार 24
- वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में बनेगा 100 करोड़ रुपए की लागत का भव्य स्मारक 25
- 'चंदेरी महोत्सव' का शुभारंभ 5 अक्तूबर से 26
- 'मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना' 27
- ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिये मध्य प्रदेश को मिला सीम अवॉर्ड 28
- रीवा में ईको-पार्क का हुआ लोकार्पण 29
- वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्र अधिसूचित 30
- अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने एशियन गेम्स के टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक 30
- मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय 31
- मेपकास्ट में साइंस सेंटर का हुआ उद्घाटन 33
- प्रदेश का पहला बायो-टेक्नोलॉजी पार्क जावद के आमलीभाट एवं बरखेड़ा में लेगा आकार 34
- भदभदा में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र 35
- पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने जीते दो अवॉर्ड 35
- प्रदेश की तीसरी मेट्रो सिटी बनेगा जबलपुर 36
- 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं को उनके निवास स्थान पर किया जाएगा सम्मानित 37

The Vision

नोट :

मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन'में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रुपए की 'कायाकल्प योजना' को स्वीकृति प्रदान करने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद द्वारा 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' की कनेक्शनधारी बहनों को 4 जुलाई, 2023 से 31 अगस्त, 2023 तक की अवधि में प्राप्त की गई गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया।
  - लगभग 40 लाख गैस रिफिल प्राप्त करने वाली बहनों के आधार लिंक बैंक खाते में प्रति रिफिल लगभग 500 रुपए के मान से राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पर लगभग 200 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों की सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिये 1200 करोड़ रुपए की 'कायाकल्प योजना'की स्वीकृति प्रदान की गई। नगरीय क्षेत्रों में नागरिकों के सुलभ आवागमन हेतु अच्छी, मज़बूत और आरामदेह सड़कों का नेटवर्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
  - इस योजना में निकाय की प्रमुख सड़कों के नवीनीकरण, मज़बूतीकरण और निर्माण का कार्य, समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा।
  - योजना के कार्यों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये नगरीय राज्य क्वालिटी मॉनिटर की नियुक्ति के साथ ही, राज्य, संचालनालय एवं संभाग स्तर पर त्रि-स्तरीय मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है।
- मंत्रि-परिषद ने 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' के अंतर्गत विद्यार्थी के पिता/पालक की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपए से बढ़ा कर 8 लाख रुपए करने की स्वीकृति प्रदान की।
- मंत्रि-परिषद ने भोपाल शहर के पश्चिम-दक्षिण हिस्से में 40.90 कि.मी. लंबे पश्चिम भोपाल बाइपास का निर्माण 2 हज़ार 981 करोड़ 65 लाख रुपए लागत से हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किये जाने का निर्णय लिया।
  - इस बाइपास मार्ग का चार लेन मय पेव्हड शोल्डर में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा निर्माण किया जाएगा।
  - परियोजना में चार लेन मार्ग के साथ 6 लेन स्ट्रक्चर एवं दोनों ओर दो लेन सर्विस रोड का निर्माण किया जाएगा। मार्ग के एकरेखण में आने वाले 1 आरओबी, दो फ्लाई ओवर, पंद्रह अंडरपास एवं दो बृहद् जंक्शन का निर्माण किया जाएगा।
  - प्रस्ताव के अनुसार निवेशकर्त्ता एजेंसी को निर्माण कार्य के दौरान ठेके की 40 प्रतिशत राशि का भुगतान 5 किश्तों में किया जाएगा। शेष 60 प्रतिशत राशि का भुगतान छ:माही एन्यूटी के रूप में अगले 15 वर्षों तक किया जाएगा।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स'की तर्ज़ पर 'खेलो एम.पी. यूथ गेम्स'को प्रदेश में प्रतिवर्ष आयोजित करने और आयोजन व्यय 200 करोड़ रुपए की सहमति प्रदान की गई।
- मंत्रि-परिषद द्वारा ज़िला रीवा में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया। नवीन अनुभाग में तहसील जवा के समस्त पटवारी हलका 01 से 87 तक कुल 87 पटवारी हल्के शामिल होंगे। जवा अनुविभाग के गठन के बाद अनुविभाग त्योंथर में तहसील त्योंथर के पटवारी हलके 01 से 100 तक, कुल 100 पटवारी हलके शेष रहेंगे।
- मंत्रि-परिषद द्वारा आशा तथा शहरी आशा कार्यकर्त्ताओं को उनके द्वारा संपादित की जाने वाली रूटीन गतिविधियों की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह 2 हजार से बढ़ाकर प्रतिमाह 6 हज़ार रुपए करने का निर्णय लिया गया। साथ ही प्रतिवर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार (अधिकतम 1000 रुपए की सीमा में) प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई है।

नोट :

- इसके साथ आशा पर्यवेक्षकों को दी जाने वाली दैनिक प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन (अधिकतम 15000 रुपए प्रतिमाह) की गई तथा प्रतिवर्ष समुचित बढ़ोतरी के निर्णय लेने के लिये विभाग को अधिकृत किया गया है।
- आशा, शहरी आशा और आशा पर्यवेक्षकों की सेवानिवृत्ति के समय दी जाने वाली राशि बढ़ाकर एक लाख रुपए की गई है। आशा, शहरी आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों के परिवारों को उनकी कर्त्तव्य अवधि में 'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना' का पात्र परिवार भी माना गया है।

- मंत्रि-परिषद द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा मध्य प्रदेश जल निगम के माध्यम से रतलाम और छतरपुर के लवकुशनगर में 2 नवीन समूह जल-प्रदाय योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इसके लिये 967 करोड़ 52 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है।मंत्रि-परिषद द्वारा मध्य प्रदेश में गुर्जरों के कल्याण, उनके सामाजिक, आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, रोज़गार, कौशल विकास एवं शिक्षा/प्रशिक्षण के लिये राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव एवं अनुशंसाएँ दिये जाने के लिये 'मध्य प्रदेश देव नारायण बोर्ड' के गठन आदेश 28 सितंबर, 2020 का अनुसमर्थन किया गया।

मंत्रि-परिषद द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा, भारिया एवं सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिये संचालित 'आहार अनुदान योजना'की पात्र महिला हितग्राहियों को महिला-बाल विकास विभाग द्वारा संचालित लाडली बहना

- योजना में समय-समय पर होने वाली राशि वृद्धि का लाभ समान रूप से देने का निर्णय लिया गया है।
- साथ ही हितग्राहियों द्वारा योजना का दोहरा लाभ लेने पर रोक के लिये आहार अनुदान योजना का लाभ लेने वाली हितग्राही महिला को लाडली बहना योजना का लाभ नहीं देने का भी निर्णय लिया गया।मंत्रि-परिषद द्वारा कपास पर मंडी शुल्क घटाकर 31 मार्च, 2024 तक 0.50 रुपए किये जाने के निर्णय का अनुसमर्थन किया गया है। यह निर्णय कपास व्यापारी एवं जन-प्रतिनिधियों की कपास पर मंडी शुल्क कम करने की मांग तथा कपास व्यापार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लिया गया।

मध्य प्रदेश के दो ग्रामों को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में मिलेंगे अवॉर्ड्स

चर्चा में क्यों ?

2 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार टूरिज्म बोर्ड के ग्रामीण पर्यटन परियोजना के अंतर्गत दो ग्राम, पन्ना के मंडला और छिंदवाड़ा के सबरवानी को आईसीआरटी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म) द्वारा विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट योगदान के लिये निर्धारित अवॉर्ड से नवाजा जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति एवं प्रबंध संचालक टूरिज्म बोर्ड शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि मंडला का सार्थक संबंधों के लिये सर्वश्रेष्ठ और स्थानीय सोर्सिंग, शिल्प और भोजन के लिये सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में नामांकन किया गया था। वहीं सबरवानी का प्रकृति के लिये सर्वोत्तम-सकारात्मक पर्यटन श्रेणी में नामांकन किया गया था।
- आगामी 30 सितंबर को नई दिल्ली में बीएलटीएम ट्रेड शो के दौरान समारोह में दोनों ग्रामों को सम्मानित किया जाएगा। यह अवॉर्ड भारतीय उप महाद्वीप क्षेत्र के लिये प्रदान किया गया है।
- रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवॉर्ड्स 2023 पुरस्कारों को चार क्षेत्रों में विभाजित किया गया है- अफ्रीका, भारत, लैटिन अमेरिका और शेष विश्व। प्रत्येक क्षेत्र के विजेता को नवंबर में होने वाले वैश्विक पुरस्कारों के लिये नामित किया जाएगा।
- आईसीआरटी, भारत पुरस्कार के लिये 6 श्रेणियाँ है-
  - प्लास्टिक कचरे के निपटान के लिये सर्वोत्तम
  - बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शन
  - स्थानीय सोर्सिंग, शिल्प और भोजन के लिये सर्वश्रेष्ठ
  - जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना
  - विविधता और समावेशन के लिये सर्वश्रेष्ठ
  - प्रकृति-सकारात्मक पर्यटन के लिये सर्वोत्तम

रीवा में खुलेगा संस्कृत विश्वविद्यालय का केंद्र

चर्चा में क्यों ?

2 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा में पत्रकार वार्ता में बताया कि शीघ्र ही ज़िले में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना लक्ष्मणबाग परिसर में की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मुख्यमंत्री 30 सितंबर को लक्ष्मणबाग परिसर में पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के केंद्र का शुभारंभ करेंगे।
- उन्होंने बताया कि प्रारंभ में पाँच पाठ्यक्रमों में पढ़ाई शुरू होगी और भविष्य में विश्वविद्यालय के रूप में विकास किया जाएगा।
- मंत्री ने कहा कि रीवा में पत्रकारों को आवासीय भूखंड प्रदान किये जाएंगे। भूखंड 1375 वर्ग फीट का होगा।
- उन्होंने कहा कि रीवा में 500 करोड़ रुपए की लागत से हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, निर्माण कार्य मार्च 2024 तक पूर्ण होगा।
- रीवा में आईटी पार्क की स्थापना के लिये 30 करोड़ रुपए मंज़ूर किये गए हैं। बहुती नहर का काम तेजी से जारी है। इससे 6 लाख एकड़ में सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी।
- जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में रीवा में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना के लिये 250 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई है। इससे कुशल व्यक्ति तैयार होंगे।

मनरेगा कार्यक्रमों के लिये जलवायु सूचना सेवा टूल- U-CRISP का मेपकास्ट परिसर में लोकार्पण हुआ

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा एवं ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एवं मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट के मुख्य आतिथ्य में मनरेगा कार्यक्रमों के लिये जलवायु सूचना सेवा टूल- U-CRISP (Universal Climate Resilience Information System and Planning Tool) का मेपकास्ट परिसर में लोकार्पण हुआ।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के सहयोग से भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह टूल विकसित किया गया है।
- मंत्री सखलेचा ने बताया कि इस टूल के माध्यम से इकोसिस्टम एवं जलवायु परिस्थितियों को समझने में सहायता मिलेगी। इस टूल के माध्यम से ग्रामों को जोड़ा जाएगा, जिससे प्राप्त सूचना का लाभ ग्रामों को मिल पाएगा। साथ ही इकोसिस्टम नेचर को समझने में इस टूल से सहायता मिल सकती है।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा एवं ब्रिटिश उप उच्चायुक्त एवं मंत्री क्रिस्टीना स्कॉट ने मेपकास्ट में एकदिवसीय कार्यशाला में जलवायु लचीलापन योजना के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर उपयोग एवं वैश्विक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्थापित नवनिर्मित रिसोर्स सेंटर का भी उद्घाटन किया।
- विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिये मेपकास्ट एवं ब्रिटिश उच्चायुक्त के बीच एमओयू किया गया। एमओयू से भविष्य में विभिन्न तकनीकी एवं नवाचार में दोनों संस्थाएँ मिलकर योजना बना सकेंगी, कार्य कर सकेंगी और नवीन प्रौद्योगिकियों को साझा भी कर सकेंगी।

- गौरतलब है कि यू क्रिस्प टूल का विकास ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार और विदेशी राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) यूनाइटेड किंगडम सरकार के इंफ्रा-स्ट्रक्चर फॉर क्लाइमेट रेजिलियेंट ग्रोथ प्रोग्राम (आईसीआरजी) पोर्टफोलियो के अंतर्गत विशेष सहयोग से हुआ है।
- आवश्यकता को देखते हुए यूनिवर्सल टूल का निर्माण, जिसके अंतर्गत अन्य देशों में भी क्लाइमेट चेंज की गतिविधियों को संपादित किया जाएगा। इस टूल को बीबीसी द्वारा 'शीर्ष 10 नवाचार टूल' में भी शामिल किया गया है।
- U-CRISP टूल जलवायु परिवर्तन की संभावित चुनौतियों का सामना करने में ग्रामीण समुदायों को आवश्यक सहायता देगा। यह ग्रामीण परिवारों को स्थानीय जलवायु डाटा को प्राप्त करने और साझा करने की सुविधा प्रदान करने के साथ ही जलवायु संकट का सामना करने में मदद करता है और उनकी आजीविका की सुरक्षा के लिये संसाधनों तक पहुँचने की सुविधा प्रदान करता है।

नोट :

- यह टूल जलवायु प्रभावों का बेहतर प्रबंधन करने में मदद के साथ ही जल-संरक्षण के निर्माण के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। साथ ही विभिन्न विभागों, जैसे- कृषि, वन, जल संसाधन आदि की विकास पहलों के तहत भूमि विकास और पौध-रोपण के कार्यों का समर्थन कर सकता है।
- इस टूल से जलवायु प्रतिरोध क्षमता योजनाएँ भी ग्रामीण क्षेत्रों को लंबे समय तक सूखे से सुरक्षित करने का समर्थन कर सकती हैं।

वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी 'माउंट एल्ब्रूज'पर लहराया तिरंगा

चर्चा में क्यों ?

1 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर (वित्त) वरुण वडेरिया ने यूरोप की सबसे ऊँची चोटी 'माउंट एल्ब्रूज' पर तिरंगा लहराया है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार वरुण वडेरिया ने इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर क्लाइंबिंग एंड माउंटेनियरिंग से मान्यताप्राप्त संस्था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरकाशी से माउंटेनियरिंग कोर्स किया है।
- वडेरिया ने बताया कि समुद्र तल से 5642 मीटर ऊँचे 'माउंट एल्ब्रूज' पर चढ़ाई काफी चुनौतीपूर्ण रही। ऊँचाई पर तापमान माइनस 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और हवा का बहाव काफी तेज़ होता है। चोटी की खड़ी चढ़ाई में हवा और ठंड आपकी कठोर परीक्षा लेती है। इसलिये यह यूरोप की न सिर्फ सबसे ऊँची चोटी है, बल्कि चुनौतीपूर्ण भी है।
- उन्होंने बताया कि एल्ब्रूज चोटी पर ऑक्सीजन और एयर प्रेशर काफी कम हो जाता है। इनके प्रभाव से साँस फूलने लगती है। लेकिन योग, प्राणायाम के कारण काफी फायदा मिला और औसत समय से पहले ही चढ़ाई पूरी कर ली।
- विदित है कि वडेरिया एक प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं, जिनका लक्ष्य सेवन समिट (सप्त चोटी) पर तिरंगा फहराना है। सेवन समिट सात पारंपरिक महाद्वीपों में से प्रत्येक के सबसे ऊँचे पर्वत हैं।

एशियन गेम्स-2022 में मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ियों का चयन

चर्चा में क्यों ?

- 4 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आगामी 23 सितंबर से 8 अक्तूबर तक चीन के हांग्जो में आयोजित होने वाले 19वें एशियन गेम्स-2022 के लिये मध्य प्रदेश के 43 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि कोविड-19 की वजह से एशियन गेम्स-2022 को स्थगित किया गया था।
- चीन के हांग्जो में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 19 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के (अकादमी के बाहर के) 11 खिलाड़ी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) के 3 खिलाड़ी, मध्य प्रदेश खेल अकादमी के 7 पूर्व खिलाड़ी तथा 3 खिलाड़ी, जो अकादमी के एसोसिएट मेंबर हैं, भारतीय टीम में शामिल हैं।
- एशियन गेम्स के लिये चयनित म.प्र. अकादमी के खिलाड़ी: इस वर्ष चीन के हांग्जो में 23 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश खेल अकादमी के सबसे ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों का चयन हुआ है।

नोट :

- केनो सेलालम: शुभम केवट, शिखा चौहान, हितेश केवट, विशाल वर्मा
- सेलिंग: नेहा ठाकुर, शीतल वर्मा, हर्षिता तोमर
- कयाकिंग-कनोईंग: अर्जुन सिंह, नीरज वर्मा, शिवानी वर्मा, कावेरी, ओ. विनीता देवी, प्राची यादव और मनीषा कौरव (दोनो पैरा केनो)
- रोईंग: रुक्मणी दांगी
- घुड़सवारी: राजू सिंह और सुदिप्ती हजेला
- शूटिंग इवेंट: ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और आशी चौकसे

- मध्य प्रदेश मार्शल आर्ट अकादमी के कपिल परमार जूडो (ब्लाईड जूडो केटेगरी) खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। अकादमी के दो एसोसिएट मेंबर दीक्षा और सपना बर्मन भारतीय एथलेटिक्स दल का हिस्सा होंगी।
- एशियन गेम्स के लिये चयनित मध्य प्रदेश के खिलाड़ी (अकादमी के बाहर के)
  - इस वर्ष आयोजित हो रहे एशियन गेम्स में अकादमी के बाहर के 11 मध्य प्रदेश के खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
  - अद्वेत पात्रे (स्वीमिंग), आध्या तिवारी, जय मीणा, तुषिता सेन और आदित्य दुबे (सभी सॉप्ट टेनिस), अनंजुल नामदेव और रोहित यादव (वुशु), दमिता देवी (कयाकिंग कनोईंग), रोहिणी कलाम (जी-जुत्सु), ज्योति चौहान (महिला फुटबॉल), आवेश खान (क्रिकेट) भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया की तुलिका और अवतार सिंह (जूडो) तथा सोनिया देवी पहीरेमबाम का (कयाकिंग-कनोईंग) में चयन हुआ है।
- इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश अकादमी के सात पूर्व खिलाड़ियों का भी भारतीय टीम में चयन हुआ है। इनमें महिला हॉकी टीम में मोनिका, सुशीला चानु, इशिका, विष्णु देवी तथा पुरुष हॉकी टीम में विवेक सागर और नीलाकांता शर्मा भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व एशियन गेम्स 2022 में करेंगे।

मध्य प्रदेश की सौर ऊर्जा क्षमता 11 गुना बढ़ी

चर्चा में क्यों ?

- 4 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप पिछले दशक में नवकरणीय ऊर्जा क्षमता में 11 गुना की बढ़ोतरी हुई है। यह राज्य की स्थापित क्षमता का लगभग 24 प्रतिशत है।

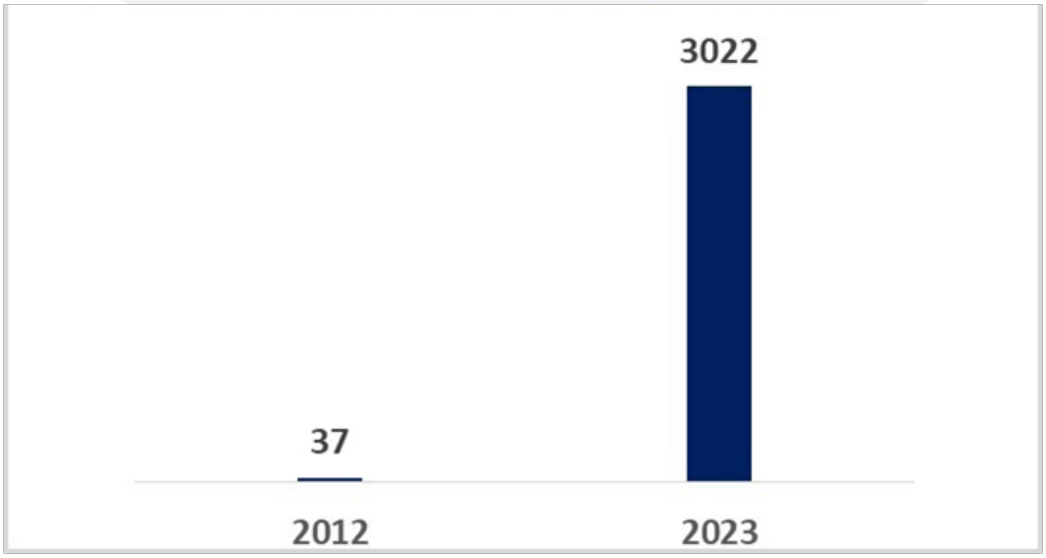

नोट :

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार प्रदेश में सौर ऊर्जा क्षमता 52 प्रतिशत बढ़ी है। वर्तमान में 1000 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क संचालित हैं और 1778 मेगावाट के पार्क जल्द ही शुरू हो जाएंगे।
- इसके साथ ही 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएँ लागू होने की प्रारंभिक स्थिति में हैं। इनमें एक हजार मेगावाट क्षमता की सोलर पार्क परियोजनाएँ (250 मेगावाट की मंदसौर सोलर पार्क तथा 750 मेगावाट की रीवा सोलर पार्क) शामिल हैं।
- विदित है कि रीवा मेगा पार्क को नवाचारी प्रयासों की वजह से कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसने प्रति इकाई 2.97 रुपए की न्यूनतम मूल्य दर हासिल की। इसे विश्व बैंक के प्रेसीडेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
- वर्तमान में 1778 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजनाओं में 1500 मेगावाट की आगर-मालवा, शाजापुर और नीमच सोलर पार्क तथा 500 मेगावॉट की नीमच पार्क परियोजना शामिल हैं।
- भविष्य की परियोजनाओं में विश्व के सबसे बड़े ओंकारेश्वर जलाशय में 600 मेगावॉट फ्लोटिंग का सोलर पार्क शामिल है। इससे साल के अंत तक पूरी तरह से उत्पादन शुरू हो जाएगा।
- इसके अलावा 3350 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं में 1400 मेगावाट की मुरैना और 450 मेगावाट की छतरपुर पार्क और बीरसिंहपुर जलाशय, इंदिरा सागर जलाशय तथा गांधीसागर जलाशय में 1500 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएँ शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश विद्युत की कमी की स्थिति को समाप्त कर भरपूर बिजली उपलब्धता की स्थिति में आ गया है। थोड़े ही समय में, मध्य प्रदेश भारत के नवकरणीय ऊर्जा के नक्शे पर चमक रहा है। राज्य सरकार की सुस्पष्ट नीतियों और मज़बूत नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश भारत की नवकरणीय ऊर्जा का मुख्य केंद्र बनने की ओर कदम बढ़ा रहा है।

मध्य प्रदेश में बढ़ती सौर ऊर्जा क्षमता (मेगावाट में)

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित हुए प्रदेश के पाँच शिक्षक

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में मध्य प्रदेश के पाँच शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2023 से सम्मानित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में देशभर के कुल 75 चयनित शिक्षकों को वर्ष 2023 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किये।
- इस शिक्षक सम्मान समारोह में सभी पुरस्कृत शिक्षकों को पुरस्कारस्वरूप 50 हज़ार रुपए नकद, प्रशस्ति-पत्र, शॉल, श्रीफल दिया गया।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह में नर्मदापुरम की सारिका घारू, इंदौर की चेतना खंबेटे, भोपाल के डॉ. यशपाल सिंह, दतिया के रविकांत मिश्रा और रतलाम की सीमा अग्निहोत्री को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया।
- नर्मदापुरम के पिपरिया स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका सारिका घारू ने जनजातीय छात्रों का नामांकन बढ़ाने के लिये अपनी कक्षा को मस्ती की पाठशाला बनाया। इनके परिश्रम से विद्यालय के जनजातीय छात्रों ने कई पुरस्कार प्राप्त किये हैं।
- इंदौर के केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, बीएसएफ की शिक्षिका चेतना खंबेटे 18 वर्षों से रुचिकर तरीके से जीवविज्ञान का अध्यापन कर रहीं हैं। इन्होंने विज्ञान प्रयोगशाला के लिये 3-डी मॉडल और इंटरएक्टिव शिक्षण सामग्री विकसित की है।
- भोपाल के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के डॉ. यशपाल सिंह को सामाजिक बदलाव लाने और शिक्षण क्षेत्र के प्रयासों के लिये पुरस्कृत किया गया। छात्रों को ज्ञान देने के साथ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों और बाल विवाह, दहेज़ जैसी कुरीतियों के विरुद्ध समाज में जागरूकता लाने का सराहनीय प्रयास किया है।
- दतिया के बीकर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के रविकांत मिश्रा को तकनीक के उपयोग से शिक्षा को सरल और रोमांचक बनाने के लिये पुरस्कृत किया गया। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाने, पीएम ई-विद्या राष्ट्रीय चैनलों पर सजीव कक्षा लेने और स्वास्थ्य जैसे महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर जागरूकता लाने जैसे कई कदम उठाए हैं।
- रतलाम के सीएम राइज शासकीय विनोबा उच्चतर माध्यमिक शाला की सीमा अग्निहोत्री को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षण सामग्री को आनंददायक बनाने के लिये सम्मानित किया गया। शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिये उन्होंने समुदाय को शामिल कर कहानी पढ़ने की प्रतियोगिता, समाचार-पत्र लेखन, नाटक और नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की है।
- राष्ट्रीय शिक्षक दिवस:
  - वर्ष 1962 से प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य भारत में स्कूल अध्यापकों, शोधकर्त्ताओं और प्रोफेसरों सहित अन्य शिक्षकों के योगदान का सम्मान करना है।
  - भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने छात्रों के उत्सव के अनुरोध की प्रतिक्रिया में उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का सुझाव दिया था।
- राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार:
  - राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के कुछ बेहतरीन शिक्षकों के अनूठे योगदान का जश्न मनाना तथा उन शिक्षकों को सम्मानित करना है, जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है।
  - ये पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किये जाते हैं।
  - पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण-पत्र एवं 50,000 रुपए की नकद राशि शामिल है।
  - इस वर्ष पुरस्कार के दायरे में स्कूली शिक्षा तथा साक्षरता विभाग द्वारा चयनित शिक्षकों के अतिरिक्त उच्च शिक्षा विभाग एवं कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चयनित शिक्षकों को भी शामिल किया गया है।

साँची बनी देश की पहली सोलर सिटी

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन ज़िले में स्थित विश्व धरोहर स्मारक स्थल साँची नगर को प्रथम सोलर सिटी के रूप में लोकार्पित किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में भी बांध की सतह पर सोलर पैनल लगाकर 600 मेगावाट क्षमता के संयंत्र स्थापित करने की पहल की गई है।
- साथ ही कार्यक्रम में नवीकरणीय विभाग और आईआईटी कानपुर के मध्य साँची को नेट जीरो सिटी बनाने के करारनामे पर हस्ताक्षर किये गए।
- साँची के पास नागौरी में तीन मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना के फलस्वरूप साँची सोलर सिटी बनी है। निकट भविष्य में गुलगांव में पाँच मेगावाट की सौर परियोजना स्थापित होगी, जो कृषि क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगी।
- साँची सोलरसिटी से वार्षिक 14 हजार टन से अधिक कार्बन डाईऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी आएगी, जो लगभग 2 लाख 38 हजार से अधिक पेड़ों के बराबर है। ईको फ्रेंडली सुविधाओं से पर्यावरण प्रदूषण रुकेगा। ई-व्हीकल को बढ़ावा दिया गया है। चार कमर्शियल चार्जिंग पाइंट तथा तीन ई-रिक्शा चार्जिंग पाइंट स्थापित कर दिये गए हैं। बैटरी वाहनों के चलने से 9 लाख से अधिक मूल्य के डीजल की भी बचत होगी।
- साँची में करीब 7 हजार नागरिकों ने अपने घरों में सोलर स्टैंड लैंप, सोलर स्टडी लैंप, सोलर लालटेन का इस्तेमाल कर बिजली बचाने का संकल्प लिया है।
- साँची में हर घर सोलर की अवधारणा सफल हुई। लगभग 63 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र घरेलू छतों पर लगाए गए हैं। शहर के केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों और प्रतिष्ठानों का इनर्जी ऑडिट करवाया गया।
- ऊर्जा साक्षरता अभियान के अंतर्गत साँची के लोगों ने ऊर्जा बचत और ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में जागरूकता का परिचय दिया। प्रतिवर्ष संयंत्रों के उपयोग से करीब 22 लाख रुपए के बिजली के बिल कम होंगे।
- साँची में नागरिकों के घरों और सरकारी कामों में व्यय होने वाले विद्युत व्यय में 7.68 करोड़ की वार्षिक बचत होगी।

नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने की अधिसूचना जारी

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सतना ज़िले की सीमाओं को परिवर्तित करने और नवीन ज़िला मैहर निर्मित करने के लिये सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश राजपत्र में सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की अवधि में लिखित में सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित की गई हैं।
- नवीन निर्मित होने वाले ज़िले मैहर का ज़िला मुख्यालय मैहर करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें सतना ज़िले की तहसील मैहर के समस्त 122 पटवारी हलका एवं तहसील अमरपाटन के समस्त 53 पटवारी हलका तथा तहसील रामनगर के 59 पटवारी हलके सहित कुल 234 पटवारी हलके रहेंगे।
- प्रस्ताव के अनुसार नवीन निर्मित होने वाले ज़िले मैहर के पूर्व में सीधी एवं रीवा, पश्चिम में पन्ना, उत्तर में सतना और दक्षिण में कटनी, उमरिया एवं शहडोल ज़िले रहेंगे।
- उल्लेखनीय है कि 5 सितंबर को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर की सभा को निवास कार्यालय समत्व से वर्चुअली संबोधित करते हुए माँ शारदा की नगरी मैहर को ज़िला बनाने की घोषणा की थी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति गठित

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2023 मध्य प्रदेश शासन ने भारत सरकार द्वारा शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च अधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- इस समिति में अपर मुख्य सचिव, वित्त, प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास, प्रमुख सचिव, लोक निर्माण, प्रमुख सचिव, पर्यटन को सदस्य एवं संचालक बजट को सदस्य सचिव बनाया गया है।
- इस समिति प्रशासकीय विभागों द्वारा प्रस्तावित ऐसी परियोजनाओं का परीक्षण कर अपनी अनुशंसा देगी, जिसके लिये शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के अंतर्गत ऋण सहायता प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हो।
- इस समिति द्वारा योजना/परियोजना की आवश्यकता उससे राज्य को होने वाले लाभ, उसकी लागत व आर्थिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता पर विचार किया जाएगा।
- यदि किसी अन्य प्रशासकीय विभाग की योजना/परियोजना शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF) के अंतर्गत ऋण सहायता की परिधि में आती है, उस स्थिति में संबंधित प्रशासकीय विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को बैठक में आमंत्रित किया जाएगा।
- यह समिति राष्ट्रीय आवास बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों को भी समीक्षा बैठक मंर आमंत्रित कर सकेगी।

नोट :

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास 'समत्व भवन' में संपन्न हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' की स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 'मुख्यमंत्री अंत्योदय आवास योजना' अब 'मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना' के रूप में जानी जाएगी।
- इस योजना को सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों के लिये मान्य किया जाएगा। भविष्य में जब-जब 'प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण' के अंतर्गत आवास निर्माण की इकाई लागत वृद्धि होगी, तब-तब इस योजना के अंतर्गत भी इकाई लागत में वृद्धि की जाएगी।
- मंत्रि-परिषद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित 'प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना' में संलग्न रसोईयों के वर्तमान मासिक मानदेय 2 हज़ार रुपए में वृद्धि करते हुए नवीन मानदेय 4 हज़ार रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है। इससे 2 लाख 10 हज़ार रसोइये लाभान्वित होंगे।
- मंत्रि-परिषद द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा दिव्यांगजनों के बैकलॉग/कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के लिये विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा में 1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2024 तक एक वर्ष की वृद्धि की गई है।
- मंत्रि-परिषद ने अतिथि शिक्षकों को दिये जाने वाले मासिक मानदेय में दोगुनी वृद्धि की स्वीकृति दी है। वर्ग-1 को वर्तमान में प्राप्त मानदेय 9 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 18 हज़ार रुपए, वर्ग-2 का मानदेय 7 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 14 हज़ार रुपए और वर्ग-3 का मानदेय 5 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपए किया गया है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में मॉब लिंचिंग के अपराध पीड़ितों और उनके आश्रितों को राहत व पुनर्वास के लिये म.प्र। मॉब लिंचिंग पीड़ित प्रतिकर योजना 2023 लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- इस योजना के तहत मॉब लिंचिंग के अपराध में पाँच या अधिक व्यक्तियों की भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, भाषा, खानपान, यौन अभिरुचि, राजनीतिक संबद्धता, जातीयता अथवा अन्य ऐसे आधार या आधारों पर हानि या क्षति कारित करने के लिये हिंसा का कोई कृत्य या कृत्यों की कोई श्रृंखला को शामिल किया गया है।
- योजना के तहत मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ितों को प्रतिकर राशि प्रदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा मुख्यमंत्री की 27 अगस्त, 2023 को की गई घोषणा के पालन में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत समस्त गैस कनेक्शनधारी महिलाओं और गैर PMUY अंतर्गत गैस कनेक्शनधारी लाडली बहनों को श्रावण मास (04.07.2023 से 31.08.2023) में गैस रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया है। लाडली बहनों के नाम से जारी गैस कनेक्शन पर श्रावण मास में कराए गए रिफिल पर अनुदान देय होगा।
- मंत्रि-परिषद ने National Forensic Sciences University (NFSU), गांधी नगर भोपाल द्वारा शैक्षणिक प्रयोजन के लिये ग्राम बरखेड़ा बोंदर तहसील हुजूर, भोपाल को कुल 4।8540 हेक्टेयर शासकीय भूमि शासन की शर्तों के अधीन नि:शुल्क प्रब्याजि और 1 रुपए भू-भाटक पर आवंटित किये जाने का निर्णय लिया है।
- मंत्रि-परिषद द्वारा 'मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना' के अंतर्गत भारत सरकार व शासन के शासकीय, स्वशासी और अनुदान प्राप्त एवं उनके विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेशित विद्यार्थियों को जेईई (JEE) मेंस परीक्षा में रैंक प्राप्त करने की बाध्यता को समाप्त किया गया है।

राज्यपाल मंगुभाई पटेल लंदन में होंगे सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 8 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्यपाल मंगुभाई पटेल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन चैप्टर द्वारा सम्मानित किया जाएगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल मंगुभाई पटेल को 14 सितंबर, 2023 को ब्रिटिश पार्लियामेंट लंदन में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
- लंदन प्रवास के दौरान राज्यपाल पटेल फ्रेड्स ऑफ मध्य प्रदेश के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे।
- विदित है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लिमिटेड, यूके एक ऐसा संगठन है, जो प्रामाणिक प्रमाणीकरण के साथ दुनिया भर में असाधारण रिकॉर्डों को सूचीबद्ध और सत्यापित करता है।
- यह एक सर्वोपरि अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जो लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिये प्रेरित करता है। यह लोगों को वैश्विक स्तर पर नए रिकॉर्ड तोड़ने या स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में छाया दमोह का शिवम छिरोलिया

चर्चा में क्यों ?

11 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार दमोह ज़िले के मड़ियादो निवासी 30 वर्षीय छात्र शिवम छिरोलिया की विपरीत परिस्थितियों में सफलता के कायल टॉपमेट कंपनी द्वारा शिवम को पूरे परिवार सहित विश्व के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जगह दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि टाइम्स स्क्वायर में नामचीन हस्तियों, फिल्मी हस्तियों के वीडियो ही दिखाए जाते हैं। शिवम छिरोलिया को पूरे परिवार सहित न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में जगह मिली है, जहाँ बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर इनका चित्रण किया गया है।
- शिवम द्वारा गाँव से निकलकर कैसे अच्छा मुकाम हासिल करें, जैसे सकारात्मक वीडियो को अपलोड किया गया था, जिसे देखने के बाद अमेरेकिन कंपनी टॉपमेट द्वारा प्रभावित होकर शिवम की कहानी न्यूयार्क में दिखाई जा रही है।
- टाइम्स स्क्वायर द्वारा अमेरिका के हृदय न्यूयार्क में शिवम की सफलता और मुकाम का वीडियो चलाकर उसकी सूचना शिवम छिरोलिया को दी गई।
- प्राथमिक शिक्षा मड़ियादो और बाद में बंगलौर आईआईएससी से शिक्षा पाने वाले शिवम छिरोलिया इस समय अमेरिकन सेमीकंडक्टर कंपनी क्वालकॉम, बैंगलोर में कंप्यूटर विजन रिसर्चर के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- शिवम ग्रामीण परिवेश से हैं, इनके पिता मनोज छिरोलिया मूकबधिर हैं और माँ गृहणी हैं। आर्थिक स्थिति से कमजोर होने के बाबजूद शिवम ने अथक मेहनत कर यह मुकाम हासिल किया।

नोट :

- विदित है कि शिवम छिरोलिया का इसरो में साइंटिस्ट बी एग्जाम में भी चयन हुआ था। इसके अलावा देश भर से रिलाइंस फाउंडेशन द्वारा चुने जाने वाले 40 योग्यताधारी में चयन हुआ था और शिक्षा के लिये छह लाख रुपए भी दिये गए थे। हालाँकि शिवम ने कंप्यूटर विजन रिसर्च पद चयन किया।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कृषक लहरी बाई को 'पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान'से किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के सी. सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में आयोजित एक कार्यक्रम में डिंडोरी ज़िले की कृषक लहरी बाई को श्रीअन्न प्रजातियों के संरक्षण और संवर्धन के लिये वर्ष 2021-22 का 'पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान'प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- लहरी बाई को कृषक अधिकार वैश्विक संगोष्ठी के अलंकरण समारोह में सम्मान स्वरूप 1,50,000 रुपए की नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र और स्मृति चिह्न प्रदान किया गया।
- विदित है कि डिंडोरी ज़िले की बजाग तहसील निवासी लहरी बाई ने बैगा समुदाय की सहायता से कोदो, कुटकी, सांवा, काग, सिकिया, मडुआ जैसे दुर्लभ श्रीअन्न प्रजातियों का सीड बैंक विकसित किया है।
- दिल्ली में 12 से 15 सितंबर, 2023 तक चलने वाली वैश्विक संगोष्ठी में लहरी बाई ने अपने सीड बैंक की प्रदर्शनी भी लगाई है।
- किसान-कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने लहरी बाई की अभूतपूर्व उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि मिलेट्स संरक्षण के लिये लहरी बाई द्वारा अद्भुत कार्य किया गया है। उनके कार्य की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रसिद्ध रेडियो प्रोग्राम 'मन की बात'में कर चुके हैं।

नोट :

मध्य प्रदेश में शुरू होगा पहला सहकारिता विश्वविद्यालय

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉ. अरविंद सिंह भदौरिया ने भोपाल में वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजना के शुभारंभ कार्यक्रम में बताया कि मध्य प्रदेश में पहला सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा।

प्रमुख बिंदु

- सहकारिता मंत्री डॉ. भदौरिया ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना पर हुई चर्चा में इंदौर अथवा भोपाल में विश्वविद्यालय शुरू करने के उनके प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में सहकारिता विश्वविद्यालय शुरू होगा। विश्वविद्यालय में सहकारिता क्षेत्र के अनेक विषयों के पाठ्यक्रमों को पढ़ाया जाएगा और सहकारिता संबंधी अनुसंधान भी होगा।
- सहकारिता मंत्री ने सहकारी प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर के नवीन भवन, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल, इंदौर और नौगाँव में सामान्य सुविधा केंद्र, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में एम्पोरिया का डिजिटल भूमि-पूजन और शिलान्यास किया। उन्होंने आर्टीजंस कार्ड का वितरण किया और वृहद हस्तशिल्प कलस्टर विकास परियोजना की पुस्तिका और पैक्स संस्थाओं के लिये तैयार पैक्स मैन्यूअल 2022 का विमोचन किया।

एग्पा, भोपाल में मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 12 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एग्पा (अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, भोपाल) में स्थापित किये गए मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र का वर्चुअल शुभारंभ तथा राज्य नीति आयोग मध्य प्रदेश द्वारा प्रकाशित एसडीजी प्रगति रिपोर्ट-2023 का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में तीन दिवसीय (11 से 13 सितंबर) सम्मेलन और कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक अर्थशास्त्री, शोधकर्त्ता और विकास से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

नोट :

- सम्मेलन के प्रमुख हिस्सों में सुशासन संस्थान में मूल्यांकन एवं प्रभाव आकलन केंद्र की स्थापना, चाइल्ड एवं जेंडर बजटिंग पर कार्यशाला, सांख्यिकी प्रणाली को मज़बूत बनाने के लिये क्षमता संवर्द्धन कार्यक्रम को भी जोड़ा गया। यह संयुक्त प्रयास प्रदेश के डेटा डिलीवरी तंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होंगे।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह केंद्र शासकीय नीतियों का असर और लोगों के जीवन में आ रहे बदलाव को देखेगा। इसके द्वारा शासकीय योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावों का आकलन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि शोध, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया डेटा उपयोगी है। यह सुशासन की नींव है और जन-कल्याण में सहायक बनता है। शोध आधारित पुख्ता सांख्यिकी आँकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं।
- मुख्यमंत्री ने एन-डीएपी अर्थात राष्ट्रीय डेटा विश्लेषिकी प्लेटफार्म की उपयोगिता पर केंद्र सरकार के नीति आयोग के सहयोग से आयोजित कार्यशाला को वर्चुअली संबोधित किया।
- उन्होंने कहा कि एन-डीएपी सरकारी डेटा की पहुँच और उपयोग में सुधार के लिये नीति आयोग की विशेष पहल है। यह प्लेटफार्म भारत के विशाल सांख्यिकी बुनियादी ढाँचे से डेटासेट एकत्र और होस्ट करता है। इसे वर्ष 2020 से 2022 से मध्य विकसित किया गया है।
- एन-डीएपी का उपयोग कर मध्य प्रदेश डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफार्म (एमपी-डीएपी) को एक एग्रीगेटर प्लेटफार्म के रूप में विकसित किये जाने पर विचार किया जाएगा। यह सम्मेलन एन-डीएपी की उपयोगिता और इसके इस्तेमाल के लिये कार्यशाला के संयोजन का महत्त्वपूर्ण माध्यम बना है।

लाडली बहनों को घरेलू गैस कनेक्शन गैस सिलेंडर रिफिल 450 रुपए में मिलेगा

चर्चा में क्यों ?

- 13 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' में पंजीकृत ऐसी लाडली बहनें, जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं, उन्हें 1 सितंबर, 2023 से गैस सिलेंडर रिफिल 450 रुपए में उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी करते हुए प्रक्रिया निर्धारित कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनांतर्गत गैस कनेक्शनधारी समस्त उपभोक्ता और गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना श्रेणी में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में पंजीकृत ऐसी लाडली बहनें, जिनके स्वयं के नाम से घरेलू गैस कनेक्शन हैं, इसके लिये पात्र होंगी।
- गैस सिलेंडर रिफिल के लिये अनुदान राशि पात्र कनेक्शनधारियों को 1 सितंबर, 2023 से देय होगी। बकाया राशि पात्र लाडली बहनों के खातों में डाली जाएगी।
- अनुदान राशि
  - पात्रताधारी उपभोक्ताओं को प्रतिमाह अधिकतम एक रिफिल पर अनुदान मिलेगा।
  - पात्रताधारी उपभोक्ताओं को ऑयल कंपनी से रिफिल निर्धारित फुटकर विक्रय दर पर क्रय करना होगा।
  - भारत सरकार द्वारा दिये गए समस्त अनुदान तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फुटकर विक्रय दर (450 रुपए) को कम करने पर शेष राशि राज्य अनुदान के रूप में पात्रताधारी उपभोक्ताओं के आधार लिंक बैंक खाते में अंतरित की जाएगी।
  - एलपीजी रिफिल की फुटकर विक्रय दर में परिवर्तन होने पर राज्य अनुदान भी परिवर्तित होगा।
- मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के पोर्टल पर ऐसी बहनों को पंजीयन किया जाएगा, जो पूर्व से गैस कनेक्शनधारी हैं। ऐसी बहनें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की भी लाभार्थी हो सकती हैं। पंजीयन का कार्य उन सभी केंद्रों पर किया जाएगा, जहाँ मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन होता है।
- पंजीयन के लिये गैस कनेक्शन कंज्यूमर नंबर एवं एलपीजी कनेक्शन आईडी आवश्यक होंगे। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का पंजीयन आईडी योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की पहचान का कार्य सभी ऑयल कंपनी से प्राप्त डाटा के आधार पर शासन द्वारा भी किया जाएगा।
- शासन की ओर से स्वत: पंजीकृत हितग्राहियों की जानकारी 25 सितंबर, 2023 से पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी तथा समय-समय पर उसे अद्यतन किया जाएगा।

नोट :

- कैसे होगी अनुदान गणना ?
  - प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी के लिये ऑयल कंपनी द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन नंबर एवं उनके द्वारा माहवार प्राप्त रिफिल का डाटा प्रतिमाह विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
  - गैस रिफिल प्राप्तकर्त्ता उपभोक्ताओं को राशि 450 रुपए में रिफिल उपलब्ध कराने के लिये देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जाएगी। अनुदान राशि की गणना के बाद कुल राशि का भुगतान विभाग द्वारा संबंधित ऑयल कंपनी के बैंक खाते में किया जाएगा।
  - ऑयल कंपनी द्वारा उपभोक्ता के आधार लिंक बैंक खाते में अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा। ऑयल कंपनी द्वारा हितग्राहीवार अनुदान भुगतान की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी।
  - 4 जुलाई, 2023 से 3 अगस्त, 2023 तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से किया जाएगा।
  - गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कनेक्शनधारी के लिये गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत लाडली बहनों का आईडी डाटा ऑयल कंपनी को उपलब्ध कराया जाएगा।
  - ऑयल कंपनी द्वारा गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी गैस कनेक्शन के डाटा का मिलान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत लाडली बहना के डाटा से किया जाएगा तथा ऑयल कंपनी द्वारा उनके गैस कनेक्शन नंबर, प्राप्त रिफिल एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। उपरोक्त डाटा के आधार पर देय अनुदान की गणना विभाग द्वारा की जाएगी।
  - विभाग द्वारा गैर पीएमयूवाई में गैस कनेक्शनधारी लाडली बहना योजना अंतर्गत पंजीकृत लाडली बहनों के द्वारा रिफिल प्राप्त करने पर देय अनुदान की राशि का भुगतान उनके आधार लिंक बैंक खातों में किया जाएगा। आवश्यकतानुसार इस व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।
- 4 जुलाई, 2023 से 3 अगस्त, 2023 तक गैस सिलेंडर रिफिल कराने वाली गैर-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत घरेलू गैस कनेक्शनधारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत पंजीकृत लाडली बहनों को भी अनुदान राशि का अंतरण इसी प्रक्रिया से किया जाएगा।
- शिकायत निवारण तंत्र
  - योजना के अंतर्गत पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को राज्य अनुदान का भुगतान में आने वाली कठिनाईयों एवं समस्याओं को दर्ज एवं निराकरण करने के लिये विभाग द्वारा ऑनलाईन एप्लीकेशन बनाया जाएगा।
  - इस एप्लीकेशन पर प्राप्त शिकायतों के निराकरण के लिये विभाग द्वारा व्यवस्था की जाएगी।
- राज्यस्तरीय मॉनीटरिंग
  - योजना के क्रियान्वयन के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग नोडल विभाग होगा। मैदानी स्तर पर कलेक्टर के निर्देशन में विभागीय अमले द्वारा योजना की मॉनीटरिंग की जाएगी। राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग के लिये प्रमुख सचिव, खाद्य की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ऑयल कंपनी के अधिकारी भी सम्मिलित होंगे।
  - हितग्राहियों के पंजीयन कार्य में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अमले का सहयोग प्राप्त किया जाएगा।
  - गैस कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को राशि 450 रुपए में रिफिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की प्रत्येक स्तर पर विभिन्न माध्यम से जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक गैस एजेंसी, स्थानीय निकायों एवं उचित मूल्य दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को देय अनुदान की सूचना प्रदर्शित कराई जाएगी।
  - ऑयल कंपनी से प्राप्त डाटाबेस के आधार पर वर्णित प्रक्रिया के अनुसार पात्र हितग्राहियों को अनुदान का भुगतान होगा, भले ही उनका पृथक् से पंजीयन न हुआ हो। हितग्राही डाटाबेस में विसंगति, अगर हो तो उसका यथोचित निराकरण कर पात्र हितग्राही को अनुदान का भुगतान किया जाएगा।

नोट :

प्रख्यात चिकित्सा शोध जर्नल 'द लानसेट' का अब मध्य प्रदेश में हिन्दी में भी होगा प्रकाशन

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2023 को हिन्दी दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने चिकित्सा जगत् में विश्व प्रख्यात जर्नल 'द लानसेट'जल्द ही हिन्दी में भी प्रकाशित करने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग ने 'द लानसेट'की डिप्टी पब्लिशिंग हेड फियोना मेकलेव और एलजीवियर पब्लिकेशन इंडिया के प्रमुख शंकर कौल के साथ बताया कि एमबीबीएस की अंग्रेज़ी पुस्तकों का हिन्दी में लिप्यान्तरण का कार्य कर रहा 'हिन्दी चिकित्सा प्रकोष्ठ मंदार' ही जर्नल के हिन्दी रूपांतरण कार्य को संपादित करेगा।
- इसके लिये शीघ्र ही अधिकृत एमओयू किया जाएगा, जो आगामी तीन वर्ष (2024-27) के लिये होगा, जिसकी कार्यवाही प्रचलन में है।
- ज्ञातव्य है कि 'द लानसेट' विश्व का सबसे प्रमुख एवं सबसे प्रभावशील शोध जर्नल है।
- इस जर्नल के हिन्दी रूपांतरण को लेकर विगत कई दिनों से हुई चर्चा के परिणामस्वरूप अब चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश और 'द लानसेट'- रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया का हिन्दी भाषा में भी रूपांतरण करेंगे।
- 'द लानसेट'अंग्रेज़ी भाषा के साथ ही स्पेनिश और पुर्तगाली में भी प्रकाशित किया जाता है। वहीं अब हिन्दी विश्व की चौथी भाषा होगी, जिसमें इसका प्रकाशन होगा।
- 'द लानसेट'- रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल के हिन्दी में उपलब्ध होने से चिकित्सा विद्यार्थियों एवं चिकित्सकों को शोध के क्षेत्र में भी रिसर्च कंटेंट स्थानीय भाषा में मिल सकेगा।
- इस जर्नल के ट्रांसलिट्रेशन का कार्य हिन्दी प्रकोष्ठ चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सकों द्वारा किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश ने देश में पहली बार हिन्दी में मेडिकल की पढ़ाई प्रारंभ की है।

प्रधानमंत्री ने बीना में 51 हज़ार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में सागर ज़िले में स्थित भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) की बीना रिफाइनरी परिसर में लगभग 51 हज़ार करोड़ रुपए के पेट्रोकेमिकल परिसर की आधारशिला रखी और अन्य नवीन औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इनमें बीना रिफाइनरी परिसर में 49 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से पेट्रो-केमिकल कॉम्प्लेक्स और प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर 1800 करोड़ रुपए की लागत की 10 नई औद्योगिक परियोजनाएँ शामिल हैं।
- लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली यह अत्याधुनिक रिफाइनरी लगभग 1200 केटीपीए (किलो-टन प्रति वर्ष) एथिलीन और प्रोपलीन का उत्पादन करेगी, जो वस्त्र, पैकेजिंग और फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण घटक हैं।
- इससे देश की आयात निर्भरता कम होगी और यह प्रधानमंत्री के 'आत्मनिर्भर भारत'के विज़न को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम होगा। यह मेगा परियोजना रोज़गार के अवसर पैदा करेगी और इससे पेट्रोलियम क्षेत्र में डाउनस्ट्रीम उद्योगों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने दस परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी, जिनमें नर्मदापुरम ज़िले में 'विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र', इंदौर में दो आईटी पार्क, रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में छह नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं।
- 'विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र, नर्मदापुरम' 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और यह इस क्षेत्र में आर्थिक विकास एवं रोज़गार सृजन की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम होगा।
- इंदौर में लगभग 550 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला 'आईटी पार्क 3 और 4' आईटी और आईटीईएस क्षेत्र को बढ़ावा देगा तथा यह युवाओं के लिये रोज़गार के नए अवसरों का भी सृजन करेगा।
- रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया जाएगा और इसकी वस्त्र, ऑटोमोबाइल एवं फार्मास्यूटिकल्स जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों के लिये एक प्रमुख केंद्र बनने की परिकल्पना की गई है। यह पार्क दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ा होगा। इससे पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा, जिससे युवाओं के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के अवसर पैदा होंगे।
- राज्य में संतुलित क्षेत्रीय विकास और समान रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छह नए औद्योगिक क्षेत्र लगभग 310 करोड़ रुपए की संचयी लागत से शाजापुर, गुना, मऊगंज, आगर मालवा, नर्मदापुरम और मक्सी में भी विकसित किये जाएंगे।

मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान

चर्चा में क्यों ?

14 सितंबर, 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार कुल 17 हज़ार 999 मीट्रिक टन के साथ मध्य प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 591 ग्राम प्रतिदिन है। यह उपलब्धता राष्ट्रीय औसत प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 444 ग्राम से 147 ग्राम अधिक है।
- मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में लगातार बढ़ोतरी पशुपालन विभाग द्वारा पशु स्वास्थ्य, सुरक्षा और विभिन्न रोज़गार मूलक योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप हुई है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के प्रथम चरण में 25 लाख 63 हज़ार और द्वितीय चरण में 208 लाख गो-भैंस वंशीय पशुओं का टीकाकरण किया गया, जो देश में सर्वाधिक है।
- गो-भैंस वंशीय पशु बछिया/पड़िया में 13 लाख 89 हज़ार ब्रूसेल्ला टीकाकरण में भी प्रदेश, देश में प्रथम है।
- देश में सबसे अधिक 3 लाख 77 हज़ार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है।
- प्रदेश में अब तक 36 लाख 47 हज़ार 482 पशुओं का लंपी के विरुद्ध टीकाकरण किया जा चुका है।
- वर्तमान में प्रदेश में भोपाल, रीवा और सीहोर ज़िले में लंपी के लगभग 80 एक्टिव केसे हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री ने 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने योजना का शुभारंभ कर भोपाल की ममता चौहान और दीपक बंसल के आवेदनों का पोर्टल पर पंजीयन कराकर योजना की पंजीयन प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने 15 सितंबर को आरंभ की गई गैस सिलेंडर रिफिलिंग योजना में शर्मिला बाई और संगीता सोलंकी का पंजीयन भी कराया।
- विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूटे परिवारों को 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' में आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना आवास योजना' बहनों के सुख और सम्मान के लिये उठाया गया बड़ा कदम है। योजना में प्रधानमंत्री आवास, आवास प्लस में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
- इस नयी आवास योजना का लाभ 4 लाख 75 हज़ार से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। विभिन्न आवास योजना के लाभ से वंचित परिवारों के लिये बनायी गई इस योजना का लाभ सभी वर्गों के आवासहीन पात्र परिवारों को मिलेगा।
- योजना की पात्रता:
  - ऐसे परिवार, जिनके आवेदन प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस एप पोर्टल पर स्वत: रिजेक्ट हो चुके हैं।
  - ऐसे परिवार, जो भारत सरकार के एमआईएस पोर्टल पर दर्ज होने से छूट गए हैं।
  - ऐसे परिवार जो सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना 2011 एवं आवास प्लस की सूची में शामिल नहीं हैं तथा उन्हें किसी भी सरकारी योजना में आवास नहीं मिला है।
  - योजना में ऐसे परिवार भी शामिल होंगे जिनके पास पक्की छत वाले मकान नहीं है अथवा जो दो कमरों तक के कच्चे मकानों में निवासरत हैं।

नोट :

- ऐसे परिवार जिनकी मासिक आय 12 हज़ार रुपए से कम है तथा परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता नहीं है।
- 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित और 5 एकड़ से अधिक और असिंचित कृषि भूमि होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
- जिन परिवारों के पास मोटर युक्त चौपहिया वाहन हैं, वे इस योजना के लिये पात्र नहीं होंगे।
- परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, तो भी इस योजना की पात्रता नहीं होगी।

- आवश्यक दस्तावेज़ में समग्र आईडी, आधार नंबर, बैंक खाता, मनरेगा जॉब कार्ड (यदि उपलब्ध हो), लाड़ली बहना योजना का पंजीयन क्रमांक (केवल लाड़ली बहनों के लिये) शामिल हैं। इन सभी दस्तावेज़ों को आवेदक को स्वयं सत्यापित करना होगा, किसी अन्य से सत्यापित कराने की आवश्यकता नहीं है।
- प्राप्त आवेदनों को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। ज़िला पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद राज्य सरकार द्वारा पात्र परिवारों को आवास आवंटन की कार्यवाही की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'पीएम विश्वकर्मा योजना' का किया शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 'पीएम विश्वकर्मा योजना' के शुभारंभ अवसर पर मध्य प्रदेश की कुम्हार अनीता प्रजापति का सम्मान किया। प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि का लोकार्पण भी किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा योजना की टैग लाइन, प्रतीक-चिन्ह और पोर्टल को लांच किया तथा कारीगरी की 18 विधाओं पर केंद्रित 18 डाक टिकटों और टूल-किट बुकलेट का विमोचन किया। प्रधानमंत्री ने 18 विधाओं से जुड़े कारीगरों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया।
- प्रधानमंत्री के जन्म-दिवस पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से वर्चुअली शामिल हुए। भोपाल में रविंद्र भवन में हुए कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिल भारतीय दस्तकारी परीक्षा में प्रदेश की आईटीआई के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया। प्रथम स्थान वाली दो छात्राओं बैतूल की अंकिता, ग्वालियर की सपना कुशवाहा तथा दो छात्रों भोपाल के विवेक साहू और ग्वालियर के हेमंत राठौर सहित कुल 20 प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित किया।
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
  - इस योजना से देश के कौशल-तंत्र को राष्ट्र के कारीगरों की ज़रूरतों के अनुरूप ढाला जा रहा है। योजना का लाभ उठाकर परंपरागत कारीगर अपनी स्किल को स्केल दे पाएंगे।
  - योजना से हर ज़िले के कुशल कारीगरों और कामगारों को प्रशिक्षण एवं आर्थिक सहायता देकर, उनके हुनर, कला और प्रतिभा को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा।

नोट :

- योजना में ज़िला स्तर पर बढ़ई, लोहार, सुनार जैसे शिल्पकारों और कारीगरों का कौशल सत्यापन किया जाएगा। आवश्यकतानुरूप इन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। प्रशिक्षण में हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा।
- प्रशिक्षण एवं कौशल सत्यापन के बाद इन्हें पीएम विश्वकर्मा प्रमाण-पत्र दिया जाएगा। हर लाभार्थी को 15 हज़ार रुपए टूल-किट के लिये दिये जाएंगे। अपना व्यवसाय प्रारंभ करने या बढ़ाने के लिये आसान ऋण सुविधा दी जाएगी।
- पहले चरण में 5% की दर से एक लाख रुपए का कोलेटरल-फ्री ऋण, दूसरे चरण में तीन लाख रुपए का ऋण प्रावधान है।
- कारीगर की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिये। योजना का लाभ प्रत्येक परिवार के एक सदस्य तक ही सीमित रहेगा। सरकारी सेवा में कार्यरत कोई भी व्यक्ति या उसके रिश्तेदार पात्र नहीं होंगे।

प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिये संचालित छात्रावासों की रैंकिंग में सीहोर ज़िला प्रथम

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा यूट्यूब लाइव कार्यक्रम में प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिये संचालित छात्रावासों की सत्र 2022- 23 की रैंकिंग जारी की गई, जिसमें सीहोर ज़िले ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र धनराजू एस ने बताया कि छात्रावासों के शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाना शासन की प्राथमिकता है। इस रैंकिंग प्रणाली को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य रहवासी सुविधाओं के साथ छात्रावासों में अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्थाओं हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जाग्रत करना है।
- संचालक धनराजू ने बताया कि छात्रावासों के प्रदर्शन एवं कार्यक्षमता के मानकों पर कुल 100 अंकों में यह रैंकिंग तैयार की गई है।
- रैंकिंग में स्वीकृत छात्रावासों की कार्यक्षमता के लिये 20 अंक, स्वीकृत सीटों पर नामांकन के लिये 20 अंक, छात्रावास के बच्चों के राष्ट्रीय मींस कम मेरिट छात्रवृत्ति में प्रदर्शन के लिये 20 अंक, ओलंपियाड में प्रदर्शन के लिये 20 अंक एवं वार्षिक परीक्षा परिणाम के लिये 20 अंक निर्धारित किये गए हैं।
- कार्यक्षमता एवं प्रदर्शन के आधार पर जारी रैंकिंग के अनुसार सीहोर ज़िले ने प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, वहीं रायसेन, देवास, डिंडोरी, मंडला, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर एवं धार क्रमशः प्रथम दस शीर्ष ज़िलों में हैं।
- इसके साथ ही प्रदेश भर के छात्रावासों की भी रैंकिंग जारी की गई है। इसमें अलीराजपुर ज़िले के ग्राम जोहट का कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, छात्रावास प्रथम स्थान पर है।

10वें विज्ञान मेले में एम.पी. ट्रांसको के स्टाल को मिला द्वितीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को भोपाल के बी.एच.ई.एल. स्थित दशहरा मैदान में आयोजित चार दिवसीय राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में आकर्षण का केंद्र बने एम.पी. ट्रांसको (मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी) के विविध जानकारियों से भरपूर स्टाल को सरकारी क्षेत्र के स्टॉल की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- एम.पी. ट्रांसको की ओर से अधीक्षण अभियंता एस के दुबे, राजेश शांडिल्य, डी.एस. बिसेन, आर.सी. शर्मा, कार्यपालन अभियंता अतुल नाबर, ए.के. श्रीवास्तव, सहायक अभियंता आशीष जैन ने भोपाल में इस राज्य स्तरीय विज्ञान मेले के समापन अवसर पर यह पुरस्कार प्राप्त किया।
- एम.पी. ट्रांसको ने ट्रांसमिशन लाइनों के मॉडल के साथ गैस इंसूलेटेड सबस्टेशन, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, वर्किंग मॉडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑनलाइन स्काडा, ऑनलाइन कैमरा डिस्प्ले आफ जी आई एस सबस्टेशन, फॉल्ट लोकेटर, परंपरागत एयर इंसुलेटेड सबस्टेशन के साथ मल्टी सर्किट ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न उपकरणों को मेले में मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया।

नोट :

- इसके अलावा विभिन्न ग्राफिक्स, पोस्टर आदि के माध्यम से एम.पी. ट्रांसको की उपलब्धियों और विविध जानकारियों को भी प्रदर्शित किया गया।

वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में बनेगा 100 करोड़ रुपए की लागत का भव्य स्मारक

चर्चा में क्यों ?

- 18 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान कहा कि आगामी 5 अक्तूबर को रानी दुर्गावती के 500वें जन्मदिवस पर मदन महल की ज़मीन पर 100 करोड़ रुपए की लागत से भव्य स्मारक का भूमि-पूजन किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- यह भव्य स्मारक रानी दुर्गावती के शौर्य, वीरता, सेवा, सुशासन एवं गौरव का प्रतीक होगा तथा युगों-युगों तक रानी की स्मृति को जीवंत रखेगा।

- मुख्यमंत्री ने अपने जबलपुर प्रवास के दौरान वेटनरी ग्राउंड में आयोजित 1857 की क्रांति के जनजातीय नायक राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर लोगों को संबोधित करते हुए यह बात कही।

नोट :

- मुख्यमंत्री ने कहा कि अमर क्रांतिकारी राजा शंकरशाह और उनके पुत्र कुँवर रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया और उनके खिलाफ संघर्ष का बिगुल फूँका। उनके इसी शौर्य एवं पराक्रम से भयभीत होकर अंग्रेजों ने उन्हें तोप के मुँह के सामने रखकर उड़ा दिया।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजातीय नायकों के बलिदानों को स्मरण करने के लिये प्रतिवर्ष प्रदेश शासन द्वारा 18 सितंबर को शहीद दिवस का आयोजन किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री ने गोंड साम्राज्य की शासिका वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य गाथा का उल्लेख करते हुए बताया कि रानी दुर्गावती ने अपने शौर्य और सामर्थ्य से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें मदन-महल, गढ़ा मंडला, सिंग्रामपुर शामिल हैं। उन्होंने मुगल शासक अकबर से भी वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों की आहूति दी, पर मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की।

'चंदेरी महोत्सव' का शुभारंभ 5 अक्तूबर से

चर्चा में क्यों ?

19 सितंबर, 2023 को प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति और प्रबंध संचालक म.प्र. टूरिज्म बोर्ड शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अशोकनगर ज़िले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल चंदेरी में 'चंदेरी महोत्सव' का औपचारिक शुभारंभ समारोह 05 अक्तूबर को होगा।

प्रमुख बिंदु

- शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश की समृद्ध कला एवं संस्कृति को प्रचारित करने, स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर सृजित करने, विकासोन्मुखी गतिविधियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चंदेरी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।
- सनसेट डेजर्ट कैंप के सहयोग से आयोजित होने वाले महोत्सव के पहले संस्करण में लोक कला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ख्यात कालाकारों द्वारा लाइव संगीत की प्रस्तुति, डीजे नाइट्स और रोमांचित करने वाली साहसिक गतिविधियाँ भी होंगी। पर्यटकों को प्राकृतिक सौंदर्य के बीच लग्जरी ग्लैंपिंग का अनुभव मिलेगा।
- अशोकनगर ज़िला प्रशासन के सहयोग से हो रहे चंदेरी महोत्सव में क्षेत्र की समृद्ध विरासत और उत्कृष्ट हथकरघा परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
- चंदेरी महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ समारोह 05 अक्तूबर को चंदेरी किले पर होगा। प्रथम पाँच दिन विशेष आयोजन होंगे, जिसमें देशभर से आने वाले ट्रेवल एजेंट्स, टूर ऑपरेटर्स, होटेलियर सहित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों को आमंत्रित किया जाएगा।
- चंदेरी पहुँचने वाले पर्यटक साहसिक गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे, शाम को लक्ष्मण मंदिर में महा आरती होगी। महोत्सव में सांस्कृतिक एवं रोज़गारन्मुखी कार्यशालाएँ भी होंगी।

नोट :

- डीजे नाइट्स और लाइट्स एंड साउंड शो, हॉट एयर बैलून ग्लो शो, विंटेज कार रैलियाँ और फोटोग्राफी वर्कशॉप जैसी गतिविधियाँ आयोजित की जाएंगी। टेंट सिटी में आने वाले पर्यटकों को चंदेरी से 4 किमी. दूर 'वस्त्र एवं शिल्प पर्यटन ग्राम'प्राणपुर का स्थानीय भ्रमण भी करवाया जाएगा।
- लोग चंदेरी में साड़ियों को बनते देख सकेंगे, योग एवं मेडिटेशन सत्र रहेंगे। साथ ही मेला मैदान में क्रिकेट और वॉलीबॉल टूर्नामेंट जैसे विभिन्न आयोजन भी होंगे।
- मेहमानों के मनोरंजन के लिये सांस्कृतिक कार्यक्रम, कला प्रदर्शनी, लाइट एंड साउंड शो, हॉट एयर बलून ग्लो शो, डीजे नाइट, लाइव बैंड एवं म्यूजिक कॉन्सर्ट, योग एवं मेडिटेशन, विंटेज कार रैली, प्राणपुर गाँव भ्रमण, भील कला पर कार्यशाला, फोटोग्राफी कार्यशाला, बोटिंग, स्टोरी-टेलिंग सेशन, महा आरती, एडवेंचर, ग्रामीण एवं कृषि पर्यटन कार्यशाला, मोन्यूमेंट विजिट, फेशन शो, राजा रानी महल, कवि सम्मेलन, स्थानीय व्यंजनों पर कार्यशाला जैसी गतिविधियाँ होंगी।

'मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना'

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को स्थाई कृषि पंप कनेक्शन देने के लिये 'मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना'में हितग्राहियों से फार्म भरवाने के कार्य का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कुशाभाऊ ठाकरे सभागृह में हुए राज्यस्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने हरदा ज़िले के ग्राम जिनवानिया की नमिता रनवे और भैंरूदा सीहोर के प्रेमनारायण पंवार के आवेदन भरवाकर योजना में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना का क्रियान्वयन तत्काल आरंभ किया जा रहा है।
- मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि योजना में 3 एचपी या अधिक क्षमता के स्थाई पंप कनेक्शन के लिये 200 मीटर तक की दूरी की 11के.वी. लाइन के विस्तार, वितरण ट्रांसफार्मर की स्थापना और निम्न दाब लाइन केबल विस्तार कार्य शामिल हैं।
- योजना में समस्त सामग्री सहित विस्तार कार्य और इसका संधारण विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य का 50 प्रतिशत व्यय शासन द्वारा और 50 प्रतिशत कृषक या कृषक समूह द्वारा वहन किया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की मेहनत ने ही मध्य प्रदेश को कृषि क्षेत्र में देश में अव्वल बनाया है। प्रदेश के शरबती गेहूँ, चिन्नोर चावल को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। प्रदेश में 2002-03 में खाद्यान्न उत्पादन 159 लाख मीट्रिक टन था, जो अब बढ़कर 619 लाख मीट्रिक टन हो गया है।

नोट :

- राज्य सरकार ने किसानों के लिये 0% ब्याज पर ऋण के साथ-साथ पर्याप्त बिजली और सिंचाई की व्यवस्था की है। केन-बेतवा लिंक परियोजना को स्वीकृति प्राप्त हो गई है, इससे प्रदेश में सिंचाई का रकबा और बढ़ेगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय प्रदेश में बिजली का कुल उत्पादन मात्र 2900 मेगावाट था। आज प्रदेश में 29 हज़ार मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन हो रहा है। सिंचाई क्षमता 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 47 लाख हेक्टेयर हो चुकी है, जिसे 65 लाख हेक्टेयर से अधिक करना लक्ष्य है।
- योजना के प्रावधान
  - अधोसंरचना विस्तार कार्य एवं सामग्री की व्यवस्था विद्युत वितरण कंपनी करेगी।
  - अधोसंरचना विकास के खर्च का 50% किसानों को देना पड़ेगा, 50 फीसदी खर्च राज्य सरकार/ बिजली वितरण कंपनी देगी।
  - पंप कनेक्शन के लिये ज़रूरी लाइन, ट्रांसफार्मर आदि का मेंटेनेंस भी बिजली वितरण कंपनी करेगी।
  - कृषकों के समूह यदि आवेदन करते हैं तो समूह के सदस्यों के द्वारा समानुपातिक रूप से खर्च उठाना पड़ेगा।
  - किसानों को केवल 50 प्रतिशत राशि भरनी पड़ेगी।
  - ट्रांसफार्मर एवं अन्य सामग्री की बेहतर गुणवत्ता से निर्बाध विद्युत, समस्त रख-रखाव संबंधी कार्य अब बिजली वितरण कंपनी करेगी।
  - योजना लागू होने से 2 वर्ष तक प्रभावशील रहेगी, प्रथम वर्ष में 10,000 किसानों को लाभ होगा।

ऊर्जा साक्षरता अभियान के लिये मध्य प्रदेश को मिला सीम अवॉर्ड

चर्चा में क्यों?

- 21 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को ऊर्जा साक्षरता की दिशा में किये गए अनूठे प्रयास के लिये सोसायटी ऑफ एनर्जी इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स (सीम) द्वारा नई दिल्ली में 'सीम स्टार परफार्मेंस अवॉर्ड-2022' से नवाजा गया।

प्रमुख बिंदु

- ऊर्जा साक्षरता अभियान को यह अवॉर्ड आम नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने की दिशा में उल्लेखनीय कदम उठाने के लिये दिया गया है। निगम की ओर से अतिरिक्त कार्यपालन यंत्री सुरेंद्र वाजपेयी ने अवॉर्ड ग्रहण किया।
- विदित है कि देश में पहली बार आम नागरिकों को ऊर्जा संरक्षण, नवकरणीय ऊर्जा के लाभ और मितव्ययिता सिखाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश में 25 नवंबर, 2021 को आरंभ 'ऊर्जा साक्षरता अभियान (ऊषा)' से 15 लाख से अधिक नागरिक जुड़ चुके हैं।

नोट :

- गौरतलब है कि ऊर्जा साक्षरता अभियान (ऊषा) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प देश को नेट ज़ीरो लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। देश और दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु असंतुलन और बिजली के अपव्यय से बचाने के लिये मध्य प्रदेश के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ऊषा अभियान की शुरुआत की गई है।
- देश की पहली साँची सोलर सिटी में 7 हज़ार नागरिक ऊर्जा साक्षर हुए हैं। ऊर्जा के व्यय-अपव्यय के प्रति लोगों को जागरूक करने, परंपरागत ईंधन के स्रोतों को बचाने, कार्बन उत्सर्जन कम करने, वृक्ष संरक्षण आदि के प्रति लोगों को जागरूक करने में ऊषा कारगर सिद्ध हो रहा है।

रीवा में ईको-पार्क का हुआ लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

- 24 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने रीवा में ईको-पार्क का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश ईको-पर्यटन विकास बोर्ड एवं रीवा लीजर प्राइवेट लिमिटेड के मध्य रीवा शहर में बीहर ईको-पर्यटन एवं एडवेंचर पार्क का निर्माण डीबीएफओटी मॉडल पर जन-भागीदारी से किया गया है।
- रीवा शहर से निकलने वाली बीहर नदी के टापू पर 5.20 हेक्टेयर भूमि पर यह ईको-पार्क विकसित किया गया है।
- इस ईको पार्क से पर्यटन की गतिविधियों को नई गति मिलेगी। यहाँ रोज़गार के अवसरों का भी सृजन होगा।
- उल्लेखनीय है कि महानगर की तर्ज पर रीवा में निजी पूंजी निवेश से बना ईको-पार्क प्रदेश का पहला ईको-पार्क है।
- 5.20 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्मित विश्व स्तरीय ईको-पार्क के निर्माण में ईको टूरिज़्म बोर्ड व वन विभाग का सहयोग है, जिसमें देश के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को ध्यान में रखकर सुविधाएँ विकसित की गई हैं।
- ईको-पार्क में जिप लाइन, स्काई साइकिलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कमांडो क्रॉसिंग, बर्मा ब्रिज, रोप कोर्स, छोटे बच्चों के लिये अत्याधुनिक झूले के साथ कई मनोरंजक सुविधाएँ हैं। पर्यटकों के लिये शानदार विश्व-स्तरीय कैफे, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट हैं। जिसमें विंध्य के व्यंजनों के अलावा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ भी पर्यटक उठा सकेंगे।

नोट :

वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्र अधिसूचित

चर्चा में क्यों ?

- 22 सितंबर, 2023 को भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा वन्य-प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन की दृष्टि से मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना की प्रदाय की गई स्वीकृति में अधिरोपित की गई शर्त के पालन में ज़िला सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर में पूर्व से अधिसूचित नौरादेही अभयारण्य को वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित किया है।
- वीरांगना दुर्गावती अभयारण्य मध्य प्रदेश का सातवाँ टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व का 1414.00 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कोर क्षेत्र तथा 925.120 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- अधिसूचित बफर क्षेत्र में नौरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभयारण्यों का पूर्व से अधिसूचित ईको सेंसेटिव जोन एवं आस-पास के वनक्षेत्र को शामिल किया गया है।
- इस टाइगर रिजर्व में अन्य कोई नया राजस्व क्षेत्र शामिल नहीं किये जाने के कारण टाइगर रिजर्व के आस-पास के स्थानीय लोगों पर कोई अतिरिक्त प्रतिबंध नहीं लागू किये जाएंगे। टाइगर रिजर्व में पूर्व से ही अधिसूचित अभयारण्य क्षेत्र अथवा ईको सेंसेटिव क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- इस टाइगर रिजर्व की स्थापना से इन वनों से प्राप्त होने वाली पारिस्थितिकीय सेवाओं
- (Eco-system Services) की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी, जो वर्तमान
- भावी पीढ़ियों के लिये पारिस्थितिकीय सुरक्षा प्रदान करेगी।

अकादमी के ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने एशियन गेम्स के टीम इवेंट में जीता स्वर्ण पदक

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शूटिंग अकादमी ऑफ एक्सीलेंस के स्टार शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने चीन के हांग्जाऊ में चल रहे 19वें एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया।

नोट :

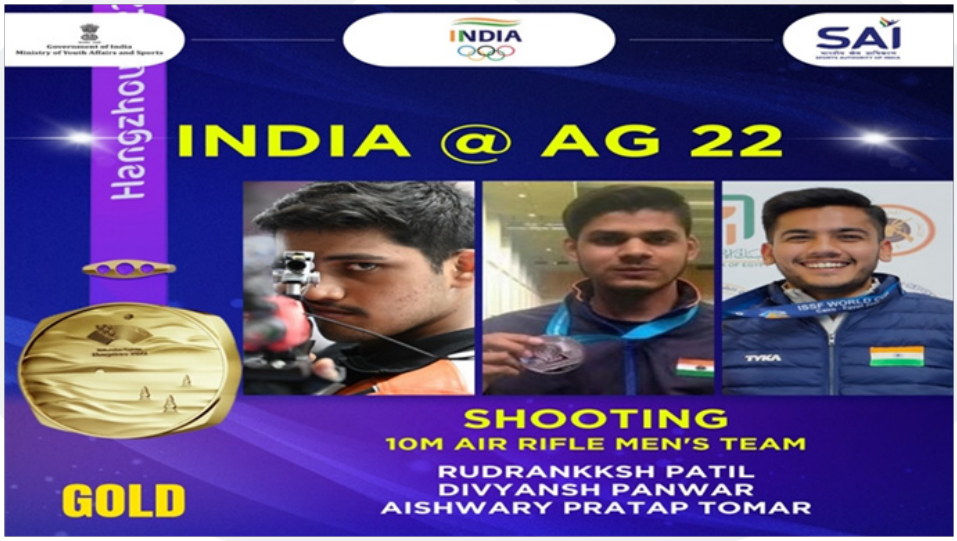

प्रमुख बिंदु

- टीम इंडिया के दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और रुद्राश पाटिल की तिकड़ी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में 1893.7 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता है। पहले यह रिकॉर्ड चीन के पास था।
- ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में 631.6 अंकों का योगदान कर भारतीय टीम को स्वर्ण पदक दिलाया। एशियन गेम्स में ही 10 मीटर राइफल एकल इवेंट में ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने 228.8 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर कांस्य पदक हासिल किया।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के महत्त्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना' एवं 'कायाकल्प द्वितीय चरण योजना' की तीन वर्षों के लिये स्वीकृति के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है कि मध्य प्रदेश के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह दी जाने वाली सम्मान निधि 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपए की जाएगी।
  - सम्मान निधि प्राप्त करने वाले पत्रकार की मृत्यु होने पर उनकी पत्नी/पति को एकमुश्त 8 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी।
  - पत्रकारों को स्वयं अथवा आश्रितों के उपचार के लिये सामान्य बीमारियों के लिये आर्थिक सहायता प्रावधान 20 हज़ार से बढ़ाकर 40 हज़ार रुपए और गंभीर बीमारियों के लिये 50 हज़ार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जाएगा।

  आयकर वाली शर्त को भी हटाया गया है।
  - उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करने वाले प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल, डिजिटल मीडिया में काम कर रहे पत्रकारों तथा मीडिया प्रतिनिधियों के समग्र कल्याण एवं हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने 7 सितंबर, 2023 को 'पत्रकार समागम' के दौरान विभिन्न घोषणाएँ की थीं।
- मंत्रि-परिषद ने पूर्व में लागू मध्य प्रदेश में अधिमान्य पत्रकारों को आवास ऋण पर ब्याज अनुदान योजना को संशोधित कर नवीन योजना 'अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण एवं शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना 2023' को स्वीकृत किया।
  - नई योजना में अधिकतम ऋण राशि सीमा 25 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए की गई है। साथ ही योजना में अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के बेटे/बेटियों की शिक्षा के लिये बैंक से लिये गए ऋण पर देय ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 वर्ष के लिये राज्य शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया है।
- मंत्रि-परिषद ने यह निर्णय भी लिया कि 'मध्य प्रदेश संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना' में पत्रकारों से वर्ष 2022-23 के लिये भारित प्रीमियम दर के अनुसार ही इस वर्ष भी प्रीमियम राशि ली जाएगी।
  - बीमा कंपनी द्वारा बढ़ाए गए प्रीमियम की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।
  - इस योजना में नए प्रावधान के अनुसार 65 वर्ष से अधिक उम्र के पत्रकारों और उनकी पत्नी/पति के बीमा का पूरा प्रीमियम राज्य शासन वहन करेगा।
- मंत्रिपरिषद द्वारा विशेष केंद्रीय सहायता (शहरी सुधार कार्यक्रम) से प्रदेश में मास्टर प्लान की सड़कों के लिये नवीन पूंजीगत योजना 'कायाकल्प द्वितीय चरण (मास्टर प्लान की सड़कें) योजना' की तीन वर्षों के लिये स्वीकृति दी गई है।
  - योजना में वर्ष 2023-24 के लिये 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण, स्मार्ट सिटी एवं एम.पी. यू.डी.सी. के द्वारा किया जाएगा।
- मंत्रिपरिषद ने जल जीवन मिशन का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा किये जाने का अनुमोदन किया।

नोट :

- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में आईटी, आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्र में निवेश को और आकर्षक बनाए जाने के उद्देश्य से निवेश नीति 2016 के स्थान पर नवीन नीति 'मध्य प्रदेश आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन 2023' का अनुमोदन किया गया।
  - क्रियान्वयन के लिये नियम एवं दिशा-निर्देश जारी करने तथा नियमों एवं दिशा-निर्देशों में सामान्य संशोधन, विसंगति दूर करने और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को अधिकृत किया गया है।
  - नवीन नीति के प्रभावशील होने से राज्य में निवेश की संभावनाओं का विस्तार होगा एवं इच्छुक कंपनियाँ निवेश के लिये आकर्षित होंगी।
- मंत्रि-परिषद द्वारा जबलपुर में दो नवीन तहसील पोंडा और कटंगी, ज़िला मऊगंज में नवीन तहसील देवतलाब तथा ज़िला ग्वालियर में नवीन तहसील पिछोर के सृजन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही ज़िला मुरैना में नवीन अनुविभाग पोरसा के गठन की स्वीकृति दी गई है।
- महिला फुटबॉल के प्रोत्साहन के लिये मंत्रिपरिषद द्वारा 'पेट्रॉन स्टेट प्रोग्राम'के संचालन के लिये 97 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।
  - योजना के क्रियान्वयन के लिये फुटबाल प्रशिक्षक एवं प्रबंधन की व्यवस्था राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ से करने तथा अन्य सपोर्ट स्टॉफ आदि की व्यवस्था निजी एजेंसी से आउटसोर्स के आधार पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा श्रम विभाग के अंतर्गत 'मुख्यमंत्री संबल खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना'को स्वीकृति दी गई। योजना अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर संबल परिवार के सदस्यों द्वारा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 50 हज़ार रुपए और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर 25 हज़ार रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश में टेक्सटाईल पार्क के निर्माण के लिये भारत सरकार को प्रेषित प्रस्ताव का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ग्राम भैंसोला ज़िला धार में पी. एम. मित्र पार्क की स्थापना का अनुमोदन दिया गया है।
  - पार्क की स्थापना के लिये भारत सरकार एवं राज्य शासन के मध्य 21 मई, 2023 को निष्पादित एम.ओ.यू. का कार्योत्तर अनुमोदन दिया गया है।
  - पी.एम. मित्र पार्क भैंसोला तहसील बदनावर ज़िला धार की स्वीकृति में निहित शर्तों के अनुरूप एस.पी.वी. के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें भारत सरकार का अंश 49 प्रतिशत एवं राज्य शासन का अंश 51 प्रतिशत रहेगा। एस.पी.वी. में राज्य शासन के अंश की राशि विभागीय बजट से उपलब्ध कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  - प्रस्तावित पार्क तक सड़क, बिजली एवं पानी की सुविधा प्रदान करना तथा एस. पी. वी. के माध्यम से मास्टर डेवलपर को समतलीकृत, अतिक्रमण मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की स्वीकृति एवं उक्त सुविधा निर्माण में होने वाले अनुमानित व्यय 163 करोड़ रुपए का वहन राज्य शासन द्वारा विभागीय बजट के तहत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
  - भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पीएम मित्र पार्क के लिये विद्युत वितरण लाईसेंस की स्वीकृति प्रदान की गई है। एस.पी.वी. को पी. एम. मित्र पार्क भैंसोला तहसील बदनावर ज़िला धार में विद्युत प्रदाय हेतु एमपीपीएमसीएल से एवरेज पॉवर परचेज कॉस्ट (एपीपीसी) पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान की गई है। पार्क में स्थापित होने वाली इकाईयों को प्रचलित औद्योगिक संवर्धन नीति अनुसार सुविधाएँ एवं सहायता दिये जाने का अनुमोदन किया गया है।
- मंत्रिपरिषद् द्वारा मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के राजपत्रित अधिकारियों के लिये अधिसमय वेतनमान की स्वीकृति दी गई है।
- मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि म.प्र. के ग्राम कोटवारों के पारिश्रमिक में 25% वृद्धि की गई।
- मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन तथा महाविद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के अनुपालन में विभाग में कार्यरत् अतिथि विद्वानों के संबंध में प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मेपकास्ट में साइंस सेंटर का हुआ उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (मेपकास्ट) में साइंस सेंटर का उद्घाटन किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि मेपकास्ट का मूल कार्य विज्ञान के प्रति आम जनमानस में रुचि बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि विज्ञान जटिल है, लेकिन इसे आसानी से समझने के लिये प्रायोगिक विज्ञान की ओर जाना बहुत आवश्यक है और यह विज्ञान केंद्र इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने इस साइंस सेंटर की स्थापना आईआईटी गांधीनगर एवं आईआईटी इंदौर के सहयोग से की है।
- साइंस सेंटर के अंतर्गत विज्ञान, तकनीकी, गणित और प्रौद्योगिकी आधारित कार्यशाला एवं शो के साथ-साथ प्रतिदिन सहभागीय विज्ञान आधारित कैपेसिटी बिल्डिंग अन्य कार्यक्रम शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिये आयोजित किये जाएंगे।
- मेपकास्ट के महानिदेशक डॉ. अनिल कोठारी ने कहा कि क्रिएटिव लर्निंग सेंटर के माध्यम से मेपकास्ट में साइंस सेंटर आज की आवश्यकता के अनुरूप डू इट योरसेल्फ के साथ-साथ अभिरुचि एवं भविष्य के वैज्ञानिक पैदा करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह बच्चों में न केवल तार्किक एवं रीजनिंग को बढ़ाएगा, बल्कि विज्ञान टूरिज्म को बढ़ाने में भी यह महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।
- इस केंद्र के माध्यम से छात्रों एवं शिक्षकों के लिये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चला सकेंगे, आमजन के लिये रोज वैज्ञानिक शो होंगे, साइंटिफिक ओरिएंटेशन होगा, विभिन्न वैज्ञानिक गैलरी का निर्माण होगा और यह सब नि:शुल्क होगा।

प्रदेश का पहला बायो-टेक्नोलॉजी पार्क जावद के आमलीभाट एवं बरखेड़ा में लेगा आकार

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने बताया कि प्रदेश का पहला बायो-टेक्नोलॉजी पार्क नीमच ज़िले में जावद के आमलीभाट एवं बरखेड़ा गाँव में आकार लेगा। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने इसे मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा एमएसएमई मंत्री ओमप्रकाश सखलेचा ने कहा कि लगभग 40 एकड़ भूमि में करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह पार्क अनुसंधान के साथ विकास का एक बड़ा केंद्र तो होगा ही साथ ही, उद्योगों के लिये तकनीकी हस्तांतरण से लाखों रोज़गार सृजन का संवाहक भी होगा।
- मंत्री सखलेचा ने पार्क को नीमच के साथ ही पूरे प्रदेश के उद्योगों,नव उद्यमियों आदि के लिये सौगात बताते हुए कहा कि पार्क की स्थापना भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग की योजना में की जा रही है।
- संभवत: देश का यह 9वाँ पार्क शोध आधारित विकास की तकनीकी उपलब्ध करवाएगा। जैव तकनीकों के व्यवसायीकरण में भी यह बायोटेक पार्क अपनी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- पार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य बायो-टेक्नोलॉजी में नवीन अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है, जिसके लिये 8 उच्च-स्तरीय प्रायोगशाला स्थापित की जाएगी। इनमें फाइटोफार्मास्यूटिकल और ड्रग डिस्कवरी प्रयोगशाला, हर्बल फॉर्म्यूलेशन, पादप ऊतक संवर्धन, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन, माइक्रोबियल बायो-टेक्नोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान, जैव सूचना और फोर्टिफाइड फूड प्रयोगशाला शामिल हैं।
- पार्क से प्रदेश के इनक्यूबेटीज, उद्यमियों एवं नवाचारों को स्टार्ट-अप के लिये तैयार किया जाएगा, जिससे इनक्यूबेशन सेंटर और पार्क के माध्यम से बायोटेक क्षेत्र में व्यवसाय शुरू कर सकेंगे।
- बायोटेक पार्क मुख्यरूप से सूक्ष्म और मध्यम प्रकार के बायोटेक उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिये एक शानदार मंच होगा, जिसमें पार्क और बायोटेक इनक्यूबेशन सेंटर सार्वजनिक उपक्रम की भागीदारी के माध्यम से बायोटेक स्टार्ट-अप एवं उद्यमी बायोटेक उत्पाद की कंपनी शुरू कर सकें। पार्क के अंतर्गत कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा तथा यह रोज़गार के अनेक अवसर भी प्रदान करेगा।

नोट :

भदभदा में 25 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र

चर्चा में क्यों ?

- 26 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के जल-संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास मंत्री तुलसीराम सिलावट ने भदभदा मत्स्य प्रक्षेत्र भोपाल में 25 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 4 एकड़ भूमि पर बनने वाले एक्वा पार्क एवं अनुसंधान केंद्र का भूमि-पूजन किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्र के वित्तीय सहयोग से जलीय जीवों के प्रदर्शन, उनके जीवन अध्ययन और इससे संबंधित पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक्वा पार्क की स्थापना की जा रही है।
- इस अवसर पर मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि मध्य प्रदेश मत्स्य-पालन में अग्रणी है और मछुआरों के क्रेडिट-कार्ड बनाने में देश में प्रथम है। प्रदेश का बालाघाट ज़िला मत्स्य-उत्पादन में देश में प्रथम है।
- मंत्री सिलावट ने बताया कि मत्स्य-पालकों को रुकने और भोजन के लिये भोपाल सहित सभी ज़िलों में भवन बनाए जाने की योजना है।

पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने जीते दो अवॉर्ड

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन मंत्रालय की बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल करते हुए दो अवॉर्ड जीते हैं। प्रदेश के ग्राम मडला और खोखरा 2023 के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव के रूप में चुने गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- नई दिल्ली के भारत मंडपम् कन्वेंशन सेंटर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में पन्ना ज़िले के मडला ग्राम को स्वर्ण श्रेणी में और सीधी ज़िले के खोखरा ग्राम को कांस्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है।
- सम्मान समारोह में सचिव, पर्यटन, भारत सरकार सुश्री वी. विद्यावती द्वारा प्रशस्ति-पत्र देकर सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की ओर से अपर प्रबंध संचालक विवेक श्रोत्रिय और संचालक कौशल डॉ. मनोज कुमार सिंह ने पुरस्कार ग्रहण किया।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम-स्टे के लिये केंद्रीय नोडल एजेंसी द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी।
- प्रतियोगिता में 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 795 ग्रामों द्वारा आवेदन प्राप्त हुए थे। इसमें से 35 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में नामांकित किया गया। इन 35 ग्रामों में से शीर्ष 5 ग्रामों को स्वर्ण श्रेणी में सम्मानित किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश का मडला ग्राम भी शामिल है। 10 ग्रामों को रजत और 20 ग्रामों को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।
- पन्ना का मडला और सीधी का खोखरा ग्राम
  - पन्ना का मडला गाँव, खूबसूरत केन नदी के किनारे स्थित है, जो कि पन्ना टाइगर रिज़र्व का एक गेट भी है। सीधी का खोखरा गाँव, संजय दूबरी टाइगर रिज़र्व के बफर क्षेत्र में स्थित है।
  - दोनो गाँव ग्रामीण पर्यटन भ्रमण, होम-स्टे अनुभव, स्थानीय भोजन, कला और शिल्प में अनूठे हैं। समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य इन ग्रामों की विशेषता है।
- रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन की ग्रामीण पर्यटन परियोजना
  - मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड न केवल पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये कार्यरत् है, अपितु संतुलित और संवहनीय पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य कर रहा है। यह सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम कर मध्य प्रदेश को संपूर्ण पर्यटन अनुभव कराने वाले गंतव्य के रूप में स्थापित करता है।
  - इसी उद्देश्य को ध्यान में रख टूरिज्म बोर्ड द्वारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन का संचालन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
  - मध्य प्रदेश को विभिन्न सांस्कृतिक और भौगोलिक विशेषताओं के कारण बघेलखंड, बुंदेलखंड, चंबल, मालवा, निमाड़ और महाकौशल जैसे छः प्रमुख सांस्कृतिक अनुभव क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। इन क्षेत्रों में प्रचलित पर्यटन स्थलों के समीपस्थ 100 ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
  - इन ग्रामों में स्थानीय भ्रमण, स्थानीय वास्तुकला आधारित आवास, गैर-रासायनिक परंपरागत भोजन, कला एवं शिल्प, स्थानीय भ्रमण, सुविधाजनक आवास, स्थानीय भोजन, स्थानीय सांस्कृतिक अनुभव तथा लोकगीत, लोक नृत्य, खेल-कूद, पूजा, उत्सव एवं त्योहारों का अनुभव, कला एवं हस्तकला का अनुभव एवं पर्यटन की आवश्यकतानुसार स्थानीय लोगों का कौशल उन्नयन जैसे 6 प्रमुख अंगों के लिये ग्रामीण पर्यटन के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। मडला और खोखरा गाँव ग्रामीण पर्यटन परियोजना के तहत नवीन विकसित गाँव हैं।

प्रदेश की तीसरी मेट्रो सिटी बनेगा जबलपुर

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर शहर को हज़ारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगातें देते हुए कहा कि जबलपुर को इंदौर और भोपाल के बाद मेट्रो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर के विकास के कार्य निरंतर किये जा रहे हैं। जबलपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ मेट्रो का जाल बिछाया जाएगा, जो इसके विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में 155 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किये गए फ्लाई-ओवर के लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए यह बात कही।
- उन्होंने कहा कि जबलपुर शहर में 5 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से 116 किमी. के रिंग रोड निर्मित किये जाएंगे। जबलपुर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले फ्लाई-ओवर्स से शहर की तस्वीर बदल जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि यहाँ 450 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट टर्मिनल, 300 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे स्टेशन, 200 करोड़ रुपए की लागत से टेक्नोलॉजी सेंटर, 200 करोड़ रुपए की लागत से आई.टी. पार्क, 125 करोड़ रुपए की लागत से मदन महल टर्मिनल, 100 करोड़ रुपए की लागत से जियोलॉजिकल पार्क और 48 करोड़ रुपए की लागत से रियल साइंस सेंटर बनेगा।

नोट :

- मदन महल के प्रस्तावित संग्रहालय में वीरांगना रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊँची प्रतिमा स्थापित होगी। इसके साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक भी बनेगा, जो उनके शौर्य और वीरता के साथ आन-बान-शान का प्रतीक होगा।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकार्पित किये गये फ्लाई-ओवर को वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाएगा और जबलपुर में बरेला को तहसील तथा मझगवाँ को नगर पंचायत बनाया जाएगा।

80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं को उनके निवास स्थान पर किया जाएगा सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

- 27 सितंबर, 2023 को मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आगामी 1 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश के 80 वर्ष या इससे अधिक उम्र के मतदाताओं को सम्मानित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि ज़िलों में ज़िला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और बूथ लेवल ऑफिसर अपने-अपने क्षेत्र के 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को उनके निवास स्थान पर ही सम्मानित करेंगे।
- उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी 52 ज़िलों में 80 वर्ष से अधिक आयु के 6 लाख 52 हज़ार 746 मतदाता हैं। इसमें 2 लाख 61 हज़ार 58 पुरुष मतदाता एवं 3 लाख 91 हज़ार 680 महिला मतदाता हैं।
- प्रदेश के रीवा ज़िले में 80 वर्ष से अधिक आयु के सर्वाधिक 35 हज़ार 52 मतदाता हैं। इसके बाद इंदौर ज़िले में इस आयु वर्ग के 31 हज़ार 512 मतदाता हैं। प्रदेश के श्योपुर ज़िले में 80 वर्ष से अधिक आयु के सबसे कम 2 हज़ार 504 मतदाता हैं।
- मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजन ने बताया कि प्रदेश के 52 ज़िलों में 100 वर्ष या इससे भी अधिक आयु के कुल 5 हज़ार 253 मतदाता हैं। इनमें 1 हज़ार 492 पुरुष मतदाता एवं 3 हज़ार 761 महिला मतदाता हैं।
- प्रदेश के सीहोर ज़िले में 100 वर्ष से अधिक आयु के 318 मतदाता हैं। दूसरे स्थान पर उज्जैन ज़िला है, जिसमें इस आयु वर्ग के 316 मतदाता हैं। इस आयु वर्ग के सबसे कम 13 मतदाता श्योपुर ज़िले में हैं।
- उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह उन गाँवों में आयोजित होगा, जहाँ 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता निवासरत् हैं। कार्यक्रम ग्राम पंचायत भवन अथवा शाला भवन में होगा।
- कार्यक्रम में उन्हीं मतदाताओं को आमंत्रित किया जाएगा, जो स्वस्थ हों और कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित होने के लिये शारीरिक रूप से सक्षम हों। जो वरिष्ठ मतदाता कार्यक्रम में उपस्थित होने में असमर्थ होंगे, उन्हें उनके घर पर ही सम्मानित किया जाएगा।
- वरिष्ठ मतदाताओं की सम्मान समिति में बीएलओ, ग्राम पटवारी, स्थानीय शिक्षक, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता एवं रोज़गार सचिव शामिल रहेंगे।
- पंचायत मुख्यालय स्तर पर यदि एक-से-अधिक मतदान केंद्र ऐसे हैं, जहाँ 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता रहते हैं, तो एक ही स्थान पर कार्यक्रम किया जाएगा।गौरतलब है कि विगत वर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रदेश में शतायु मतदाताओं को सम्मानित करने का अभिनव नवाचार किया गया था। कार्यक्रम में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूपचंद्र पांडेय ऑनलाइन शामिल हुए थे और प्रदेश में हुए कार्यक्रम की सराहना की थी। कार्यक्रम के दौरान विगत वर्ष 4168 शतायु मतदाताओं को सम्मानित किया गया था।

नोट :